

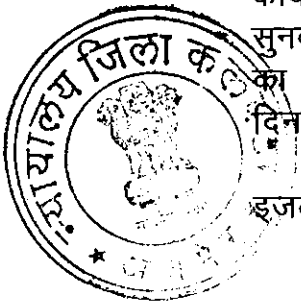


हमने उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्त ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि अपीलान्त की खातेदारी भूमि से लगती हुई है जिस पर भारी रकम लगाकर सुधार/विकास कार्य द्वारा समतल करवाकर सिंचाई हेतु बोरिंग खुदवा गया है। अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर करीब 30 वर्षों से निरन्तर काश्त की जा रही है जो राजस्व रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील सम्बत 2047, 2057, 2060, 2061 से साबित है जिसमें अपीलान्त द्वारा क्रमशः मूंग, बण, मक्का, की काश्त की गई है। राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश क्रमांक प-6(7)राज0/4/77/15 दिनांक 16.10.2001 के अनुसार 15.7.1994 तक के कब्जे को नियमन किया जा सकता है। उन्होंने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि पूर्व में खातेदारी भूमि थी, जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से सिवाय चक तथा किस्म पाल दर्ज कर दी गई। राजस्व मानचित्र एवं मौके की स्थिति के अनुसार विवादित भूमि की किस्म पाल नहीं हैं। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिचार नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये बिना, अपीलार्थी के पुराने कब्जे संबंधी जांच एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2010 निरस्त किया जावे तथा अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी के पक्ष में नियमन/आवंटन किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमाया जावे।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2010 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



(गौरव गोयल)  
जिला कलक्टर,  
अजमेर

21/01/18